एक नजर में

बुधवार को नहीं दिखा उनतिसा चांद

सिंगरौली। रमजान का चांद आसपास के इलाकों में दिखाई नहीं दिया और किसी तरह की कोई शरई गवाही भी नहीं मिली जिससे नमाजे तरावीह गुरुवार की रात बाद नमाजे ईशा शुरू हुई। शकील अहमद सिद्दीकी ने बताया कि शहर की मुख्य जामा मस्जिद अहले सुन्नत मसलके आलाहजरत में नायब इमाम अल्हाज हजरत हाफिजों कारी मुश्ताक अहमद साहब ने कुरान पाक के डेढ़ पारे पढ़ाये। रमजान के चांद को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थीं कि बुधवार शाम को चांद दिख जाएगा, क्योंकि सऊदिया अरब में मंगलवार को चांद दिखने की खबर चर्चा में थी। मगरिब के वक्त मस्जिदों की छत पर, घरों, मकानों से लोग रमजान के चांद के दीदार की कोशिश कर रहे थे लेकिन चांद नहीं दिखा। जिले के देवसर तहसील सहित आसपास के इलाकों में भी शुक्रवार से पहला रोजा शुरू होगा।

55 पाव देशी-विदेशी शराब जब्त

सिंगरौली। आबकारी विभाग ने वृत्त देवसर के अंतर्गत अवैध शराब के संग्रहण एवं विक्रय की सूचना मिलने पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही किया है। बताया गया कि कार्यवाही के दौरान ग्राम जियावन व डोंगा में दबिश के दौरान आरोपी ललन गुर्जर व राकेश साहू के रिहायशी मकान व दुकान से कुल 4 पाव गोवा व्हिस्की, 55 पाव देसी मदिरा मसाला, 16 केन बियर बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जप्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 8207 रुपये हैं।

एजेंडा जोड़ने के अधिकार पर कानूनी जंग, सदन में गरमायी बहस

नेता प्रतिपक्ष समेत भाजपा के कई पार्षदों ने बैठक से किया वाकआऊट ,कांग्रेस पार्षद ने महापौर को जमकर सुनाया खरीखोटी, दोपहर बाद बैठक शुक्रवार तक के लिए स्थगित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली19 फरवरी। नगर पालिक निगम सिंगरौली के सभागार में आज गुरूवार की दोपहर नगर परिषद अध्यक्ष देवेश पाण्डेय की अध्यक्षता में एवं आयुक्त सविता प्रधान की मौजूदगी में बैठक शुरू हुई। बैठक के शुरुआत होते ही भाजपा के पार्षद संतोष शाह ददोली ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए बैठक से वाकआऊट कर दिया। पार्षद ने कहा कि आज कई वर्षो से एनसीएल ग्राउंड मार्ग में नाली निर्माण के लिए प्रयास करता रहा। जहां नाली निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू हुआ। जहां पता चला कि नाली निर्माण कार्य हुआ नही और राशि आहरित कर ली गई। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसकी जांच के लिए निगम आयुक्त से मिलकर चर्चा भी किया लेकिन आज तक स्थिति स्पष्ट नही की गई।

उक्त पार्षद के साथ नेता प्रतिपक्ष सीमा जायसवाल,पार्षद भारतेन्दू पाण्डेय समेत अन्य कई पार्षदों ने बैठक छोड़कर चले गए। ननि अध्यक्ष देवेश पाण्डेय ने एजेण्डे पर फिर से चर्चा करने के लिए कहा जहां कांग्रेस पार्षद अखिलेश सिंह ने सीधे महापौर रानी अग्रवाल पर विफर गए। पार्षद ने कहा कि मेयर मौजूद हैं लेकिन उनके एमआईसी सदस्य बैठक में क्यों नही हैं। क्या यह बैठक अधिकृत रुप से नही बुलाई गई है और क्या मेयर नगर के विकास के प्रति गंभीर नही है,स्पष्ट करें। न्यायालय में जाने के लिए सबका अधिकार है,परंतु नगर के विकास कार्य में क्यों रोड़ा डाल रही हैं। इसके पीछे मेयर की मंशा क्या है? क्या वे नगर का विकास नही चाहती हैं,वहीं पार्षद ने यह भी मुद्दा उठाया कि पिछले दिनों खबर सुनने में आयी कि आयुक्त के द्वारा पार्षदो के साथ नगर विकास के लिए बैठक की गई है। क्या हम लोग पार्षद नही है,चुनिंदा ही पार्षदों को बैठक में क्यों बुलाया गया। हालाकि पार्षद के उक्त सवालों का नगर निगम अध्यक्ष ने जवाब दिया लेकिन उनका जवाब गोलमाल रहा। इस जवाब से पार्षद का गुस्सा ठंडा नही हुआ और एजेण्डे पर ही वार-पलटवार शुरू हो गया। मेयर रानी अग्रवाल ने उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए बताया कि एजेण्डे में अन्य बिन्दु जोड़ने का अधिकार को नही है। उन्होंने नपानि अधिनियम का हवाला भी दिया। वहीं अध्यक्ष ने आयुक्त को इसका जवाब देने के लिए कहा। जहां आयुक्त सविता प्रधान के निर्देश पर उपायुक्त आरपी वैश्य ने सदन को बताया कि परिषद की बैठक में यदि एक तिहाई पार्षद किसी बिंदु पर सहमत हैं तो उस बिंदु को एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। उपायुक्त के जवाब से मेयर नाखुश दिखी। जहां फिर से पार्षद अखिलेश सिंह ने मेयर को कहा कि आप नगर का विकास नही करता चाहती हैं। हम सब एक साल बाद फिर से जनता के बीच जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। आप ने चुनाव के वक्त क्या-क्या वायदे किए थे,एक भी वायदे क्यों नही पूरा किए?उन्होने यह भी कहा कि महापौर आप कार्यवाही बाधित न करें। करीब आठ महीने से नगर परिषद की बैठक नही बुलाई गई। आप चर्चा से भाग रही हैं। बात-बात में न्यायालय जाने की क्या जरुरत है। आप के बदौलत सिविक सेंटर का मामला न्यायालय पहुंचा है। यह काम कब होगा,साथ ही नगर निगम के निर्माणाधीन कार्य कग पूर्ण किए जाएंगे। उन्होने यहां तक कहा कि मेयर के कामकाज एवं नपानि के सिस्टम का घोर विरोध करता हूं। वहीं भाजपा पार्षदों के वाकआऊट के बाद ननि अध्यक्ष ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे तक के लिए बैठक स्थगित करने की घोषणा किया। बैठक में कार्यपालन यंत्री संतोष पाण्डेय समेत भाजपा व कांग्रेस के पार्षद मौजूद थे।

एमआईसी सदस्य व आप पार्षद भी नदारत

परिषद की बैठक में एमआईसी के सदस्यों के अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षद भी नदारत रहे। हालाकि नगर निगम के बाहर बैठक पर नजर रखे हुए थे और पल-पल की जानकारियों एमआईसी सदस्य व आप के पार्षद ले भी रहे थे। नगर निगम में ही इस बात की चर्चा है कि मेयर एवं एमआईसी सदस्य शहर के विकास के प्रति गंभीर नही है। बल्कि विकास कार्यो में रोड़ा डाल रहे हैं। जिसके चलते नगर के विकास कार्य पर इस समय संकट के बादल जहां मंडरा रहे हैं,वहीं माडल रोड के खस्ता हालात को लेकर लोगबाग मेयर पर ही निशाना साध रहे हैं। हालाकि बमुश्किल से 9 करोड़ रुपए की मंजूरी सड़क निर्माण के लिए मिली हैं। लेकिन सात महीने से बैढ़न शहरवासी खस्ताहाल सड़क से चलने के लिए मजबूर हैं।

भाजपा पार्षदों के वॉकआऊट से सब हदप्रद

नगर परिषद की बैठक निर्धारित समय से करीब ढाई घंटे बाद शुरू हुई। हालाकि इसके पहले नवनिर्वाचित पार्षद विजय शाह को पीठासीन अधिकारी एसडीएम ने पद व गोपनियता की शपथ दिलाया। इसके बाद परिषद की बैठक जैसे ही शुरू हुआ। एजेंडे पर चर्चा की बारी आई। पार्षद संतोष शाह ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सबको चौंका दिया और भ्रष्टाचार पर अपनी बात करते हुए सीधे बैठक का वाकआऊट कर दिया। इस नजारे को देख परिषद में मौजूद कर कोई हदप्रद रह गया। वहीं नगर निगम में तरह-तरह की चर्चाए चल रही थी। कोई कह रहा था कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था और कुछ कह रहे थे कि नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान है।

301 करोड़ की सौगात : सिंगरौली में तीन दर्जन सड़कें स्वीकृत

देवसर एवं सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक बजट में निर्माण कार्य शामिल

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 फरवरी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में वर्ष 2026-27 का वार्षिक आम बजट प्रस्तुत करते हुए सिंगरौली जिले को बड़ी सौगात दी गई। इस बजट में जिले की तीन दर्जन सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को मंजूरी मिली है,जिन पर कुल 301 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। वहीं उक्त कार्यों के लिए सिंगरौली,देवसर विधायक के द्वारा दिए गए मांग पत्रो को प्रदेश के वार्षिक बजट में प्राथमिकताएं दी गई हैं।

बताया गया है कि इन सड़कों को बजट में शामिल कराने में रामनिवास शाह, राजेंद्र मेश्राम तथा विश्वामित्र पाठक के सतत प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पांचो विधायकों द्वारा लगातार क्षेत्र की जर्जर सड़कों और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया गया,जिसके परिणाम स्वरूप इन मार्गों को बजट में स्थान मिला। मंजूर मार्गों में जमगढ़ी से जमगढ़ी, शिवपुरवा से शिवपुरवा, धौरहवा से सिरगुड़ी, पोड़ी बरगवां से बरहवां टोला, पचौर जेल से शिव मंदिर पहुंच मार्ग, झारा से बगीचा, मयार नदी पहुंच मार्ग, भमौरा से गहिड़ार, ननियागढ़ से मुनगहवा, मेन रोड गोभा से ननिहागढ़,कुर्सा आदिवासी बस्ती, देवसर बायपास, दुआरी से दुआरी, कुर्सा भाठ, शिवगढ़ आदिवासी बस्ती, गड़ाखाड़ से सुहिरा, खोखरी से सुहिरा, कसर नौढिया से गोरबी रेलवे फाटक तक एनएच-75, मोरवा बस्ती से एनएच-75 एक्सटेंशन, बरगवां बस्ती मार्ग, झारा से बंजारी, परासी गड़ई गांव मार्ग, गहिड़ार ढोढी टोला, खम्हरिया महदेवा टोला, समुंद छांदा से दुधमनिया बड़का डोल गोपद नदी तक मार्ग, भरसेड़ी करवाही, चिरई डोल, पिपरा कुरूंद से उर्ती,साजावार से डोंगरी, मकरोहर पीएमजीएसवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ सीमा, खनुआखास आदिवासी बस्ती, घोघरा से घोघरा, गोरबी बस्ती, निगरी जगत चौराहा से धनवाही, झारा रेलवे स्टेशन से झारा आदिवासी बस्ती, छतौली से बुधरिया टोला, छतौली से बहरी, छतौली आंतरिक मार्गए गंगा प्रसाद शाह के घर से मेवा लाल पाण्डेय के घर तक, गदसा से गदसा, आईटीआई के बगल से धतुरा और रैला बेतरिया मार्ग शामिल हैं। 301 करोड़ रुपये की इस स्वीकृति को जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

ग्रामीण, आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने से आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उक्त मंजूर सड़को एवं निर्माण कार्यो की संख्या करीब तीन दर्जन है। वहीं प्रदेश के 2026-27 के बजट में 301 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा में 32 छात्रों का चयन

प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र, बैग, ट्रैक सूट, पानी की बोतल व अन्य सामग्री का वितरण

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 फरवरी। जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले के 32 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। इन चयनित छात्रों को सम्मानित करने के लिए कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र, बैग, ट्रैक सूट, पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स सहित अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई।

इस अवसर पर बच्चों में उत्साह का माहौल देखा गया और सभी ने अपने-अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर गौरव बैनल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्तरीय परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय ओलंपियाड के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को निरंतर मेहनत करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका की भी सराहना करते हुए उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह, जिला परियोजना समन्वयक आरएल शुक्ला, सहायक परियोजना समन्वयक, बीआरसी, शिक्षकगण एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एनसीएल बीना परियोजना पर विस्थापितों का हमला बोल

रोजगार से वंचित परिवारों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

- 80 प्रतिशत स्थानीय रोजगार के आदेश की अनदेखी का आरोप
- 23 फरवरी से आमरण अनशन की चेतावनी, जिम्मेदारी कंपनी और सरकार पर

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 फरवरी। एनसीएल बीना परियोजना में कार्यरत कंपनी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग के खिलाफ विस्थापित परिवारों ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले स्थानीय लोगों को रोजगार देने के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और 23 फरवरी से आमरण अनशन की चेतावनी दी है।

ज्ञापन में छोटे लाल दुबे एवं बबुल प्रसाद दुबे निवासी ग्राम घरसड़ी, पोस्ट योगीचौरा,जिला सोनभद्र ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार की भूमि एनसीएल बीना परियोजना में अधिग्रहित की गई थी। इसके बावजूद उन्हें स्थायी रोजगार नहीं दिया गया।

उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कई बार अधिकारियों को मौखिक एवं लिखित शिकायत की गई लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी सिंगरौली, कलेक्टर ,एनसीएल महाप्रबंधक बीना परियोजना, श्रम विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजी है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 10 जुलाई 2006 के निर्देशानुसार 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय विस्थापितों को दिया जाना था किंतु कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

आरोप है कि कंपनी ने 18 फरवरी 2022 को जारी दिशा-निर्देशों की भी अनदेखी की है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिला। इससे परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

घर में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की तत्परता से टली बड़ी अनहोनी

चितरंगी के ग्राम बड़कुड़ में दहशत का माहौल, संयुक्त टीम ने पुलिस सहयोग से किया रेस्क्यू

नवभारत न्यूज

चितरंगी 19 फरवरी। वन परिक्षेत्र करथुआ अंतर्गत ग्राम बड़कुड़ में बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब एक मगरमच्छ अचानक रामबली तिवारी के घर में घुस आया। रात करीब तीन बजे घर के आंगन में मगरमच्छ को देखकर परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। परिजन किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे और तुरंत ग्रामीणों तथा प्रशासन को सूचना दी।

सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी चितरंगी रविशेखर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन परिक्षेत्र चितरंगी एवं वन परिक्षेत्र करथुआ की संयुक्त टीम गठित की गई। रेस्क्यू अभियान के दौरान थाना प्रभारी सुदेश तिवारी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की 112 टीम को मौके पर तैनात किया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रही। रेस्क्यू कार्यवाही से पहले वन विभाग की टीम ने घर के आसपास भीड़ को हटाया और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घेरा बनाया। इसके बाद विशेष उपकरणों की सहायता से मगरमच्छ को काबू में किया गया। लगभग एक घंटे तक चले इस अभियान में चितरंगी वन परिक्षेत्र से सुरेश प्रजापति वनपाल एवं भोला यादव सुरक्षा समिति, करथुआ वन परिक्षेत्र से भैयालाल नापित तथा शेरवा वन परिक्षेत्र से हरिप्रसाद सेन वन रक्षक और मुरली यादव ;सुरक्षा समिति सक्रिय रूप से मौजूद रहे। वन विभाग की टीम ने पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

लाभकारी खेती बनाने कृषि प्रशिक्षण आयोजित, किसानों ने लिया हिस्सा

नवभारत न्यूज

बरगवां 19 फरवरी। ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में हिंडालको महान एल्युमिनियम ने सीएसआर के अंतर्गत बड़ोखर,पोखरा और जोबगढ़ ग्रामों में कृषि आधारित आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

इसमें 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण रीवा के कृषि प्रशिक्षक व उद्यमी विपिन तिवारी ने किया। किसानों को रेड बनाना लाल केला, पपीता, चिया सीड्स,अरंडी तथा बड़े पैमाने पर मशरूम उत्पादन जैसी उच्च मूल्य फसलों की वैज्ञानिक खेती,लागत प्रबंधन और बाजार संभावनाओं की जानकारी दी गई। यह पहल बीज से बाजार तक 360 डिग्री मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण बीज, विशेषज्ञ सहयोग और उपज के विपणन से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में योजना पायलट आधार पर संचालित है, जिसके सकारात्मक परिणामों के बाद इसे अन्य ग्रामों में विस्तारित किया जाएगा। महान एल्युमिनियम की यह पहल खेती को लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

धिरौली में तीन दिवसीय खेल महोत्सव युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 फरवरी। ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदाणी फाउंडेशन के सहयोग से सरई तहसील अंतर्गत धिरौली में तीन दिवसीय भव्य फु टबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सिंगरौली फु टबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में 17 से 19 फरवरी तक चले इस खेल महोत्सव ने पूरे क्षेत्र को खेल उत्साह से सराबोर कर दिया।

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अदाणी समूह की विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े गांवों के युवाओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पीइकेबी परसा छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए धिरौली ब्लॉक की टीम को 2.0 से पराजित कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। मुकाबला अंतिम क्षणों तक रोमांच से भरा रहा और दर्शकों ने खिलाड़ियों का जमकर उत्साहवर्धन किया। इससे पूर्व सेमीफाइनल मुकाबलों में धिरौली कोल ब्लॉक की टीम ने अदाणी पावर, नगवा को कड़े संघर्ष में 1.0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, वहीं पीइकेबी परसा छत्तीसगढ़ ने लामा टोला, अनूपपुर की टीम को 1.0 से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। टूर्नामेंट के सफल आयोजन में जिला फु टबॉल संघ सिंगरौली के सचिव लवकुश तिवारी, धिरौली के उप-सरपंच शिशुपाल सिंह, झलरी के सरपंच दिलीप कुमार शाह, बजौड़ी उप सरपंच राकेश वर्मा, सहित आसपास के विद्यालयों के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अदाणी समूह की ओर से राधा रमण राय, बिनोद कुमार सिंह, मुनीश सूद, विक्रम शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया।

एसपी,कलेक्टर कार्यालय से 100 मीटर दूर चल रहा जुएं का अड्डा

कोतवाली के साए में आधी रात तक जुएं की महफिल, सुरक्षा घेरा बनाकर खेला जा रहा काले धन का खेल, पुलिस गश्त पर उठे गंभीर सवाल

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 19 फरवरी। जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर इन दिनों कथित रूप से जुए का गढ़ बन चुका है। आरोप है कि रात ढलते ही यहां जुआरियों की महफिल सजती है और आधी रात तक खुलेआम दांव लगाए जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब उस जगह पर हो रहा है, जहां से जिले की पूरी पुलिस व्यवस्था संचालित होती है।

स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, जुआं खेलने वालों के लिए बकायदा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। मंडी के पीछे वाले गेट पर ताला जड़ा रहता है, जबकि मुख्य द्वार पर निगरानी के लिए खास लोग तैनात रहते हैं। ये लोग बाहरी व्यक्तियों और पुलिस की संभावित गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जैसे ही किसी अनजान व्यक्ति की आहट होती है, जुआरियों को सतर्क कर दिया जाता है। इस सुनियोजित व्यवस्था से यह साफ झलकता है कि यह कोई छिपा-छुपा खेल नहीं बल्कि पूरी तैयारी और संरक्षण के साथ चलाया जा रहा अवैध कारोबार है। रहवासियों का कहना है कि रात के समय मंडी परिसर के आसपास संदिग्ध गतिविधियां अचानक बढ़ जाती हैं। वाहनों की आवाजाही, लोगों का जमावड़ा और देर रात तक हलचल आम बात हो गई है। इससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। सवाल यह उठता है कि जब इतनी संवेदनशील जगह के पास जुआ जैसा अपराध चल रहा है, तो पुलिस की नियमित गश्त और खुफिया निगरानी आखिर कहां गायब है। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि जुआरियों को कथित रूप से संरक्षण मिल रहा है, तभी एसपी कार्यालय के इतने करीब यह खेल बेखौफचल पा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन जिस तरह से गतिविधियां लगातार जारी हैं, वह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लगा रही हैं। आम नागरिक पूछ रहे हैं कि अगर यहां कार्रवाई नहीं हो सकती, तो शहर के दूर-दराज इलाकों में कानून का डर कैसे कायम होगा। प्रशासनिक दावों के बावजूद जुए का फंड रोजाना सजना यह दर्शाता है कि या तो जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं या फिर उन्हें इसकी जानकारी होते हुए भी अनदेखी की जा रही है।

पुलिस के गश्त पर खड़े हो रहे सवाल

यह स्थिति न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए खतरा है बल्कि युवाओं को अपराध की ओर धकेलने वाली भी है। जुआ जैसे अवैध धंधे से सामाजिक ताना-बाना कमजोर होता है और अपराध को बढ़ावा मिलता है। इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस की यह चुप्पी अब और सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी परिसर में रात के समय विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएं, गश्त बढ़ाई जाए और जुए के अड्डे पर कठोर कार्रवाई हो।

प्रशासन कब कसेगा शिकंजा

अब बड़ा सवाल यह है कि कानून के साए में चल रहे इस जुए के साम्राज्य पर प्रशासन कब शिकंजा कसेगा। क्या जिम्मेदार अफसर जागेंगे या फिर यह अवैध खेल यूं ही चलता रहेगा। सिंगरौली की जनता जवाब चाहती है और कार्रवाई की मांग कर रही है। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गएए तो यह मामला प्रशासन की साख पर गहरा धब्बा साबित हो सकता है।